vkj- ,u- vkbZ- u- UPHIN/2010/32566 Mkd- iath;u- l[;k& SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

o"kZ % 16 vad % 18 y[kuÅ] x:okj 14 vxLr 2025 ls 20 vxLr 2025 rd i"B&8 eY; % ,d :i;k

सेना के शौर्य को समर्पित होगा PM मोदी का भाषण?

हो सकते हैं महिला कल्याण, किसानों से जुड़े बड़े ऐलान

नई दिल्ली। भारत १५ अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। हर साल की तरह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएँगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह प्रधानमंत्री मोदी का देश के नाम लगातार १२वाँ संबोधन होगा, और लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद से यह उनका दूसरा संबोधन होगा। समारोह सुबह ७:३० बजे आधिकारिक संबोधन के साथ शुरू होगा। आमतौर पर इसकी शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों के गर्मजोशी भरे अभिवादन से होती है, जिसके बाद २१ तोपों की सलामी और जन गण मन के जोशीले स्वरों के साथ होता है, जिसे अक्सर ऊपर से भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा पुष्प वर्षा से और भी बेहतर बनाया जाता है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री के भाषण में आत्मनिर्भरता पर दोगुना जोर देने की आवश्यकता पर जोर दिया जा सकता है। इसके अलावा, मोदी जम्मू–कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले में केंद्र के रोडमैप का ऐलान भी कर सकते हैं। इस बारे में जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल सिफारिशें दे चुके

हैं। राज्य के दर्जे की बहाली की औपचारिक घोषणा के बाद विधायी और कार्यपालिका के स्तर पर तेजी से कदम बढ़ाए जा सकेंगे। सूत्रों के अनुसार राज्य का दर्जा बहाल करने के विधेयक में मौजूदा विधानसभा को राज्य विधानसभा के तौर पर आगे बढ़ाने का प्रावधान होगा। मोदी हर साल अपने भाषण में ऐसे बड़े ऐलान करते हैं, जिनसे देश को दिशा मिले। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया आदि का ऐलान भी स्वतंत्रता दिवस पर ही हुआ है। सेना का शौर्य इस बार का संबोधन ऑपरेशन सिंदूर सेना द्वारा दिखाए गए शौर्य को समर्पित होगा। मोदी आतंक के खिलाफ भारत की नई रणनीति अंतरराष्ट्रीय समुदाय को बताएंगे। पीएम इसके कूटनीतिक और राजनीतिक पहलू बताएंगे। मोदी महिला कल्याण की नई योजना और किसान सम्मान निधि को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसका रोडमैप तैयार है। सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के बारे में भी घोषणाएं हो सकती हैं। मोदी भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का रोडमैप भी दे सकते हैं, ताकि टैरिफ वॉर के बीच दुनिया हमारी ताकत महसूस करे।

'भारत मां, महापुरुषों, क्रांतिकारियों और वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता का भाव है तिरंगा यात्राः मुख्यमंत्री'

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश आजादी के ७८वर्ष पूरे कर रहा है। आजादी के इस अमृतकाल में हर भारतीय के मन में संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीयता, क्रांतिकारियों–महापुरुषों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव और प्रगाढ़ हो। यह हर जन, हर घर तक पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से इसे हम सभी देख रहे हैं। तिरंगा यात्रा केवल यात्रा नहीं, बल्कि भारत मां, महापुरुषों, क्रांतिकारियों और वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। हर गांव, नगर, जनपद में तिरंगा यात्रा इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। यूपी में भी हर घर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा से जुड़ रहे हैं। भारतीयों का दायित्व बनता है कि भारत का सम्मान ऊंचा बनाए रखें। सीएम ने अपील की कि १४० करोड़ भारतवासी स्वयं के स्वार्थों की तिलांजलि देकर राष्ट्रमाता के चरणों में समर्पित होकर तिरंगा को हर घर पर लगाकर देश की आजादी

के इस समारोह में भागीदार बनें। सीएम ने कहा कि सामाजिक एकता को छिन्न–भिन्न करने का कुत्सित प्रयास करने वालों तथा समाज, क्षेत्र, भाषा, जाति समेत अनेक वादों के नाम पर बांटने वाले तत्वों को बेनकाब करें। सीएम योगी ने कहा

'मुख्यमंत्री ने किया तिरंगा यात्रा का नेतृत्व, युवाओं संग ली सेल्फी'

मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सहयोगियों व जनप्रतिनिधियों संग हाथ में तिरंगा लेकर श्भारत मां की जयकार, वंदे मातरमश की गूंज के साथ यात्रा का नेतृत्व किया। सीएम ने अपने आवास से तिरंगा यात्रा को रवाना भी किया। इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स, स्काउट गाइड्स, युवाओं आदि के साथ सेल्फी भी ली। तिरंगा यात्रा को देख लग रहा था कि लखनऊ की सड़कों पर समूचा भारत उमड़ पड़ा है।

देश और सैनिकों के सम्मान तथा आन–बान–शान का प्रतीक तिरंगा हर भारतीय के घर में लहराया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 'हर घर तिरंगा' अभियान (१३–१५ अगस्त) का शुभारंभ किया। राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुनों के बीच मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया, फिर अपने आवास से यात्रा को रवाना किया। सीएम ने युवाओं का अभिनंदन करते हुए सभी को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के शौर्य, पराक्रम, सामर्थ्य और शक्ति को दुनिया ने देखा है। इसे लेकर जब दुनिया अचंभित है तो हर कि प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया २०४७ तक का विराट लक्ष्य 'विकसित भारत–आत्मनिर्भर भारत' सभी के सामने है। सीएम ने कहा कि उनके संकल्पों के साथ जुड़कर 'विकसित उत्तर प्रदेश–आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा व मंत्र बनाएंगे। समारोह में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कपिलदेव अग्रवाल, विधायक नीरज बोरा, जया देवी, ओपी श्रीवास्तव, विधान परिषद सदस्य महेंद्र सिंह, मुकेश शर्मा, उमेश द्विवेदी, भाजपा के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, भाजपा नेता नीरज सिंह आदि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने H५ एवियन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के सम्भावित खतरे के दृष्टिगत सम्बन्धित विभागों को त्वरित और समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां H५ एवियन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के सम्भावित खतरे के दृष्टिगत सम्बन्धित विभागों को त्वरित और समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संरक्षित पशु–पक्षियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी प्राणि उद्यानों, पक्षी विहारों, नेशनल पार्कों, वेटलैण्ड क्षेत्रों और गो–आश्रय स्थलों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जाए। उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार की गाइडलाइनों के अनुरूप सभी आवश्यक कदम तत्परता से लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्राणि उद्यान परिसरों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर ब्लो टॉर्चिंग की प्रक्रिया भी अपनायी जाए। सभी वन्य जीवों और पक्षियों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से हो और उनके आहार की गहन जांच के बाद ही भोजन उपलब्ध कराया जाए। बाड़ों में नियुक्त कर्मचारियों की ड्यूटी जोखिम के स्तर को देखते हुए तय की जाए, ताकि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन हो सके। मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों को एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण, संक्रमण के तरीके और उससे बचाव के उपायों

की विस्तृत जानकारी दी जाए। कर्मचारियों को पी०पी०ई० किट सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वे सुरक्षित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोल्ट्री सेक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश के सभी पोल्ट्री फार्मों की मानकों के अनुरूप कड़ी निगरानी की जाए तथा पोल्ट्री उत्पादों के आवागमन पर निरन्तर नियंत्रण रखा जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को H५ एवियन इन्फ्लुएंजा के मानव स्वास्थ्य पर सम्भावित प्रभावों का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि संक्रमण की कोई श्रृंखला मानव समाज तक न पहुंच सके। मुख्यमंत्री जी ने केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, स्वास्थ्य मंत्रालय, मत्स्यपालन एवं डेयरी विभाग तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (बरेली) सहित अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सतत संवाद बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि इन संस्थानों से प्राप्त सुझावों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समय पर समन्वित एवं सख्त कार्रवाई ही भ५ एवियन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के सम्भावित संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त करेगी। सभी सम्बन्धित विभागों को आपसी सहयोग, समन्वय और त्वरित सूचना के आदान–प्रदान के साथ कार्य करना होगा, ताकि प्रदेश के नागरिकों और वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सम्पादकीय

कारोबार पर लटक रही तलवार

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति की दर जुलाई में आठ साल के सबसे निचले स्तर– यानी १.५५ प्रतिशत रही। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर को अलग कर दें, तो कोर यानी मुख्य मुद्रास्फीति दर ४.१ फीसदी रही, जो जून में ४.४ प्रतिशत थी। यानी कुल मिलाकर महंगाई बढ़ने की दर में गिरावट का ट्रेंड है। बहरहाल, इससे यह ध ारणा नहीं बननी चाहिए कि असल में महंगाई घट रही है। ताजा सरकारी आंकड़े सिर्फ यह कहते हैं कि महंगाई अब पहले की तुलना में कम तेजी से बढ़ रही है। महंगाई दर जुलाई २०२४ में जिस स्तर पर थी, अब उससे १.५५ प्रतिशत ऊपर है, लेकिन चूंकि पहले महंगाई इससे काफी अधिक तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए इस दर में आई गिरावट को राहत की खबर समझा गया है। बहरहाल, असल सवाल यह है कि क्या इससे आम उपभोग में बढ़ोतरी होगी, ताकि बाजार में मांग बढ़े? इसकी संभावना कम है, क्योंकि मुद्रास्फीति दर कम रहना तब मांग को प्रोत्साहित करता है, जब आम आमदनी मुद्रास्फीति की तुलना में अधि ाक बढ़े। ऐसा होने का संकेत नहीं है। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर बढ़ रही चुनौतियां हैं, जिनकी वजह से ताजा राहत अल्पकालिक साबित हो सकती है। अमेरिका के टैरिफ युद्ध के कारण अनेक कारोबार पर तलवार लटक रही है, जहां बड़ी संख्या में रोजगार जाने का अंदेशा है। वैसी स्थिति में आम आमदनी में और गिरावट आएगी। गौरतलब है, उपभोग और मांग का ना बढ़ना हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या रही है। केंद्र ने इसका समाधान निकालने की जरूरत को नजरअंदाज किया है। जबकि पेट्रोलियम पदार्थों के सस्ते आयात का लाभ आम उपभोक्ताओं को देकर तथा जीएसटी दरों में अनुकूल संशोधन कर वह ऐसा करने की स्थिति में है। फिलहाल, सरकार चाहे तो ऐसे कदम उठा कर मुद्रास्फीति दर में गिरावट से बनी अनुकूल स्थिति का लाभ उठा सकती है। खाने–पीने की चीजों की महंगाई नियंत्रित रहे और सरकार की पहल से लोगों की जेब में पैसा बचे, तो उस स्थिति में वे अवश्य ही अधिक उपभोग के लिए प्रेरित होंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में गति आएगी।

रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में पांच लोगों की मौत

जौनपुर। जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी पेट्रोल पंप के पास एक रोडवेज बस और ट्रक की आमने–सामने की टक्कर में दो साल की बच्ची समेत पांच लोगों की मौत हो गई और लगभग १५ अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना मंगलवार रात खेतासराय थाना क्षेत्र के गुरैनी पेट्रोल पंप के पास हुई। अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटना रात करीब साढ़े १० बजे हुई जब जौनपुर से आ रही बस और शाहगंज से आ रहे एक ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। पुलिस अधीक्षक (एसपी) डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि मृतकों में दो महिलाएं, दो पुरुष और एक बच्चा शामिल है। पुलिस के अनुसार, इस घटना में १५ अन्य घायल हुए हैं।

'जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का करें समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण'

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव श्री एस.पी.गोयल ने जनसुनवाई पोर्टल, बाढ़ राहत और हर घर तिरंगा अभियान आदि की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधि ाकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये।अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के कड़े निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के साथ उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये। नियमानुकूल शिकायतों व मांगों, जिनमें वित्तीय उपाशय निहित नहीं है, का सकारात्मक निस्तारण किया जाए। किसी अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कम से कम एक स्तर उच्च अधिकारी से कराई जाए और शिकायत सही पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अधीनस्थ अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निस्तारण आख्या का स्वयं परीक्षण करने के उपरांत ही स्पेशल क्लोज की कार्यवाही की जाए। जनपद स्तर पर एडीएम, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, एएसपी, डीसीपी व अन्य अधिकारी को आख्या की गुणवत्ता जांचने हेतु नामित किया जाये। शिकायतकर्ता की संतुष्टि को प्राथमिकता दी जाए और त्रुटिपूर्ण स्पेशल क्लोज पाए जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध एक्शन लिया जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को माह जून व जुलाई, २०२५ के सभी स्पेशल क्लोज के प्रकरणों में से २० प्रतिशत का स्वयं परीक्षण करने तथा शेष प्रकरणों को एडीएम व एएसपी स्तर के अधिकारियों के मध्य विभाजित कर १५ दिनों के भीतर स्पष्ट आख्या शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की नियमित म नीटरिंग की जाए। आवश्यकतानुसार बाढ़ प्रभावित

क्षेत्रों में खाद्यान्न व लंच पैकटों का वितरण किया जाए। बाढ़ के दौरान हुई फसल क्षति का आंकलन तेजी से कर लिया जाए, जिससे शीघ्र मुआवजा किसानों को भेजा जा सके। जिन क्षेत्रों में जलस्तर कम हो गया है, वहां सफाई अभियान चलाया जाये। एग्रीस्टैक की समीक्षा के दौरान उन्होंने शेष १३ प्रतिशत ग्रामों के जियो–रेफरेंसिंग का कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर आगामी ३१ अगस्त से पूर्व पीएम किसान सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करायी जाये। फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण कार्य में भी प्रगति लायी जाये। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का तृतीय चरण आज से प्रारम्भ हो गया है। शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, बाधों, पुलों आदि को १३ से १५ अगस्त, २०२५ तक तिरंगा लाइटिंग से प्रकाशित किया जाये। जिन भवनों में फसाड लाइटिंग हैं, उन्हें तिरंगा थीम पर परिवर्तित कराया जा सकता है। वालंटियर्स को सक्रिय कर हर घर तिरंगा पोर्टल पर अधिक से अधि ाक संख्या में सेल्फी अपलोड करायी जाए। प्रत्येक शासकीय विद्यालयों में १५ अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित होना चाहिये। बैठक में बताया गया कि १,०८,८३५ में से ६५,६६२ ग्राम जियो रेफरेंस हो चुके हैं, अवशेष १३ प्रतिशत ग्रामों को जियो रेफरेन्स करने की कार्यवाही गतिमान है। बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती लीना जौहरी, प्रमुख सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश कुमार मेश्राम, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री मोहित अग्रवाल, प्रमुख सचिव कृषि श्री रवींद्र सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 2025: ब्रज भूमि बनेगी भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी

लखनऊ। ब्रज क्षेत्र के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (१६ अगस्त, २०२५) की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। भगवान श्रीकृष्ण के ५२५२वें जन्मोत्सव पर मथुरा और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के अनुसार, इस वर्ष केवल मथुरा में ही ५० लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। शहर में छोटे–बड़े मंच सजाए गए हैं, जिन पर १,००० के करीब कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह ने दी। उन्हों ने बताया कि मथुरा–वृन्दावन में तीन दिन शहर के मुख्य मार्ग से लेकर गलियों तक भव्य शोभा यात्राएं निकलेंगी। उत्सव के दौरान पारंपरिक झांकियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विविध गतिविधियों के माध्यम से ब्रज की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। दरअसल, १५ से १७ अगस्त तक तीन दिन की लगातार छुट्टी होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। विभाग का अनुमान है, इस वर्ष मथुरा–वृंदावन क्षेत्र में देशी–विदेशी पर्यटकों का सैलाब उमड़ेगा। पर्यटन मंत्री ने बताया कि मा० मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना और गोकुल में भव्य तैयारियां की गई हैं। जिनके माध्यम से श्रद्धालु और पर्यटक भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़ी लीलाओं का साक्षात अनुभव कर सकेंगे। हमारा प्रयास है, कि यहां आने वाला हर व्यक्ति

भक्ति, आनंद और अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव के साथ लौटे। ब्रज की समृद्ध विरासत दुनिया के कोने–कोने तक पहुंचे। जयवीर सिंह ने बताया कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भक्ति का माहौल चरम पर है। मथुरा की गलियों में श्रीकृष्ण बाल लीलाओं की झांकियां सज रही हैं। वहीं, मंदिरों को फूलों, फसाड लाइटिंग, रंगोली और दीपों से सजाया जा रहा है। १५ अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि से भव्य शोभायात्रा निकलेगी। मथुरा की गलियों से लेकर वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और गोवर्धन मंदिरों शोभायात्रा की श्रृंखला भक्तिमय वातावरण तैयार करेगी। राधा–कृष्ण मंदिरों को फूल, रंगोली और दीपों से सजाया जा रहा है। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर ब्रज और बुंदेलखंड के साथ–साथ राजस्थान व हरियाणा के लोक कलाकार नृत्य प्रस्तुत करेंगे। कार्यक्रम में राई, कच्छी घोड़ी और गुजरी नृत्य की विशेष झलक देखने को मिलेगी। वहीं इस्क न और बरसाना के राधा रानी मंदिर की भजन मंडलियां भक्ति संध्या के माध यम से श्रद्धालुओं को भाव–विभोर करेंगी। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, गोकुल, बरसाना और नंदगांव में धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विशेष तैयारियां की गई हैं। जन्माष्टमी केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि ब्रज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। पर्यटक सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए पर्यटन विभाग दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का स्वागत करेगा।

योगी सरकार ने बढ़ाया लक्ष्य, ६७.५० लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का मिलेगा लाभ

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के ६१ लाख गरीब बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन देने के अपने वादे को वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ही पूरा कर लिया है। अब योगी सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में ६७.५० लाख पात्र बुजुर्गों तक पेंशन की राशि पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इससे पहले बीते वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में ही योगी सरकार ने अपने लक्ष्य के अनुरूप ५६ लाख गरीब बुजुर्गों के खाते में १,००० रुपए प्रतिमाह की दर से पेंशन की राशि देकर उनकी आर्थिक सहायता कर चुकी है। योगी सरकार ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वर्ष २०२५–२६ में वृद्धावस्था पेंशन योजना में पेंशनरों का लक्ष्य ६१ लाख निर्धारित किया था, जिसे पहले ही वित्तीय वर्ष में प्राप्त कर आगे का नया लक्ष्य तय किया है। इस महत्वपूर्ण फैसले से योगी सरकार ने प्रदेश के बुजुर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। साथ ही सिंगल नोडल अकाउंट (एसएनए) प्रणाली ने पेंशन की प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया है, जहां पेंशन सीधे आधार–लिंक्ड खातों में जाती है, बिना किसी मध्यस्थ के। इससे सरकारी धन का सदुपयोग सुनिश्चित होता है और लाभार्थी बिना देरी के लाभ पाते हैं। एसएनए प्रणाली का इस्तेमाल न केवल वितरण को तेज करता है, बल्कि अ डिट और ट्रैकिंग को आसान बनाता है। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है और हर पैसे का हिसाब रखा जाता है। वृद्धावस्था पेंशन योजना योगी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का प्रमुख हिस्सा है, जो बुजुर्गों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने पर केंद्रित है। इस योजना के तहत ६० वर्ष से अधिक उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजनों को प्रतिमाह १,००० रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे उनके जीवन के अंतिम वर्षों में वित्तीय परेशानियां कम होती हैं। योगी सरकार ने इस योजना को शुरू से ही

प्राथमिकता दी है। २०१७ में जब योजना का विस्तार शुरू हुआ, तब लाभार्थियों की संख्या ३७.४७ लाख थी, जो आज ६७.५० लाख के लक्ष्य तक पहुंच गई है। यह वृद्धि सरकार की सक्रियता का नतीजा है, जहां विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र बुजुर्गों को चिह्नित किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यदि तय लक्ष्य से अधिक पात्र मिलते हैं, तो उन्हें भी योजना में शामिल किया जाता है। इस योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्ष २०१८–१९ में ४०,७१,५८० वृद्धजनों को इस योजना का लाभ मिला, जिसमें १,८७,६१३.१० लाख रुपए की ध नराशि खर्च की गई। २०१९–२० में यह संख्या बढ़कर ४७,६६,४८० हो गई और २,६६,७७४.४५ लाख रुपए का व्यय हुआ। २०२०–२१ में ५१,२४,१५५ लाभार्थियों को ३,६६,४४६.१३ लाख रुपए की पेंशन मिली। २०२१–२२ में ५१,६२,७७६ वृद्धजनों को ४,२७,७६०.५६ लाख रुपए की पेंशन दी गई। २०२२–२३ में यह संख्या ५४,६७,२३७ तक पहुंच गई, और इस पर कुल ६,०८,३७४.५० लाख रुपए खर्च हुए। २०२३–२४ में ५५,६८,५६० वृद्धजनों को इस योजना का लाभ मिला है और इस पर कुल ६,४६,४३४.०६ लाख रुपए की धनराशि खर्च हो चुकी है। वहीं, वर्ष २०२४–२५ में ५५,९६,६६७ लाख लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिला। इस वर्ष की पहली तिमाही में ही लक्ष्य प्राप्ति से साफ है कि योगी सरकार बुजुर्गों के आत्मसम्मान और आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ने योजना को और सुलभ बनाया है। एसएसपीवाई डैश यूपी डॉट गॉव डॉट इन वेबसाइट पर कोई भी पात्र व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी आवेदन की पुष्टि करते हैं। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा ५६,४६० रुपए और ग्रामीण में ४६,०८० रुपए है। यह योजना गरीब बुजुर्गों के लिए वरदान साबित हो रही है।

दिव्यांगजन रोजगार अभियान के तहत लखनऊ में आयोजित किया गया

लखनऊ। दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें मुख्यध ारा से जोड़ने के उद्देश्य से दिव्यांगजन रोजगार अभियान के अंतर्गत आज डॉ. शकुंतला मिश्रा

राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में दिव्यांगजन हेतु रोजगार मेला आयोजित किया गया। यह अभियान ६ से १३ अगस्त २०२५ तक प्रदेशभर में चलाया जा रहा है। मेले का शुभारंभ उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मिशन निदेशक पुलकित खरे ने मुख्य विकास अधिकारी अजय जैन की उपस्थिति में फीता काटकर किया। मिशन निदेशक ने मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और प्रतिभागियों से संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मिशन का प्रयास है कि दिव्यांगजन को बराबरी के अवसर मिलें और वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। ऐसे मेले उन्हें अपने हुनर को पहचानने और सही अवसर प्राप्त करने में मदद करते हैं। उन्होंने नियोक्ताओं से आह्वान किया कि दिव्यांगजनों को भी सामान्य युवाओं की तरह क्षमतावान मानते हुए अधि ाक से अधिक संख्या में सेवायोजित किया जाए। इस मेले में **Vardhman TeÛtiles Ltd, Amazon, TMC, Billions of Mind, Mega Mind Solution, Jail Café, Ambika Creation, V&Mart, Agaes Federal Life, Saubhagya Foundation Trust] Real Virasat Infracorb Pvt-Ltd-, Media Pvt- Ltd-, Tumble Dry, SEDAC, MaÛ Life Insurance** सहित २५ कंपनियों ने भाग लिया। इन कंपनियों ने १५०० से अधिक रिक्तियों के लिए ३२५ दिव्यांग प्रतिभागियों का साक्षात्कार किया, जिनमें से १७२ प्रतिभागियों को नौकरी के ऑफर दिए गए। रोजगार मेले में समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र (ब्त्ब्) ने दिव्यांगजन सहायक यंत्रों का प्रदर्शन किया और पुनर्वास सेवाओं की जानकारी दी। इसके अलावा डैडम् विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया का मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम में आई.टी.आई. अलीगंज के प्रधानाचार्य एवं जिला समन्वयक राज कुमार यादव, सहायक सेवायोजन अधि ाकारी प्रज्ञा त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रतिभागियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई।

कबाड़ हो चुके पुरानें वाहनों के लिए स्क्रैप सेंटर बनकर तैयार बंथरा में हुआ उद्घाटन

अखिनेश दुबे

लखनऊ। वाहनों के स्क्रैप सेंटर का बंथरा के पहाड़पुर गांव में भव्य उद्घाटन किया गया है। राजधानी का पहला स्क्रैप सेंटर पीएस इंटरप्राइजेस द्वारा खोला गया। पिछले

दो वर्ष से अधिक समय में इसे तैयार किया है। जहां कबाड़ हो चुके पुराने वाहनों को निस्तारित करने का कार्य किया जाएगा। १५ वर्ष पुराने वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं जारी किया जाएगा, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी होगी और जो सड़क पर चलने लायक नहीं होंगे। इसके लिए सरकार द्वारा अतीक प लिसी लाने की तैयारी की जा रही है। ऐसे वाहनों को स्क्रैप सेंटर लाना होगा। इसके अलावा आग लगने एवं सड़क हादसे में क्षतिग्रस्त वाहनों को भी स्क्रैप सेंटर लाना होगा। इस तरह के अन्य वाहनों को निस्तारित करने के लिए वाहनों को स्क्रैप सेंटर भेजा जाएगा। स्क्रैप सेंटर के संचालक रजनीश सिंह ने बताया कि स्क्रैप सेंटर में गाड़ी के वजन, उम्र व हालत को देखते हुए उसकी कीमत लगाई जाएगी। पुराने वाहन के स्क्रैप कराने पर वाहन मालिक को नकद रकम और प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इससे नए वाहन खरीदते समय उन्हें शोरूम में छूट भी मिलेगी। राजधानी में लगभग ६ लाख वाहन १५ वर्ष पुराने हैं। वाहन स्वामियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए सरकार द्वारा स्क्रैप सेंटर खोलनें की तैयारी पूरे प्रदेश में चल रही है।

पुलिस वाहन की चपेट में आने से शौच के लिए गई महिला की मौत

अमेठी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में बुधवार तड़के शौच के लिए बाहर गई ३४ वर्षीय महिला की कथित तौर पर एक अनियंत्रित पुलिस वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। घटना मोहनगंज थाना क्षेत्र के चेतारा गांव के पास हुई। पुलिस के अनुसार, चेतारा निवासी अंजुम बानो (३४) सुबह करीब चार बजे शौच के लिए बाहर गई थीं और सड़क किनारे बैठी थीं, तभी तेज रफ्तार पुलिस वाहन ने नियंत्रण खो दिया, उन्हें टक्कर मार दी और खाई में पलट गई।

पुलिस ने बताया कि परिवार के सदस्य उन्हें तिलोई के रेफरल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मोहनगंज के थाना प्रभारी राकेश कुमार ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत अमेठी जिले को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है और दावा किया जाता है कि हर घर में शौचालय है।

वाहन ने राहगीर व मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल

ग्रेटर नोएडा। बुधवार सुबह एक वाहन ने राहगीर और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना बीटा– दो थाना क्षेत्र की है और घायल व्यक्ति की पहचान रामप्रताप नीरज के रूप में हुई है जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि आज सुबह रामप्रताप जब बीटा– दो में अपने घर से किसी काम के लिए पैदल जा रहे थे तभी एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और इसके बाद भागने की कोशिश में वाहन चालक ने एक मोटरसाइकिल को भी टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि रामप्रताप को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। उन्होंने बताया कि शुरुआत जांच में पता चला है कि वाहन चालक एक निजी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है जिसकी पहचान की जा रही है।

सदानंद तत्त्वज्ञान परिषद का विश्व कल्याण हेतु जंतर मंतर पर किया धरना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में विद्या तत्त्वम पद्धति को शामिल करने हेतु दूसरी बार धरना

(के०के० शुक्ला)

लखीमपुर खीरी/नई दिल्ली। सदानन्द तत्वज्ञान परिषद ने अधिवक्ता देबाशीष होता द्वारा दायर एक मामले पर उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार विश्व कल्याण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) में विद्या तत्त्वम पद्धति को शामिल करने हेतु बुधवार को दिल्ली के जंतर–मंतर पर दूसरी बार धरना आयोजित किया जिसमें पूरे भारत से सैकड़ों भक्त सेवक शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के सिद्धौर तहसील स्थित सदानन्द तत्वज्ञान परिषद के महात्मा कमल, महात्मा दिलेश्वरानंद, महात्मा आबिद आलम खान, महात्मा शिवानंद ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर आयोजित एक संगोष्ठी में विश्व कल्याण हेतु विद्या तत्त्वम पद्धति के अनुसार शिक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और इस बात पर दुख व्यक्त किया कि २०१५ में दिल्ली में परिषद द्वारा आयोजित ३ महीने के धरने के बावजूद सरकार ने नई शिक्षा नीति में विद्या तत्त्वम पद्धति को लागू नहीं किया है। इसलिए अधिवक्ता देवाशीष होता ने २१ अगस्त २०२३ को उच्च

न्यायालय में एक मामला दायर किया था। जिसमें होता ने तर्क दिया कि एनसीटीई ने आज तक बच्चों के नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के विकास के लिए कोई पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया स्थापित नहीं की है। इसलिए बच्चों के नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास नहीं हो सका। इसलिए जब बच्चा बालिग हो जाता है, तो उनमें से अधिकांश झूठे, हिंसक, उत्तेजित, असहयोगी, बेईमान, अनादर करने वाले, असंयमी और निर्दयी होते हैं। और उपर्युक्त मूल्यहीन व्यवहार के कारण, मानव समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। मामले की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने १२ सितंबर २०२३ को एडo होता को केंद्र सरकार के समक्ष एक उचित आवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और साथ ही केंद्र सरकार को एडo होता के उपर्युक्त आवेदन पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्या तत्त्वम पद्धति को शामिल करने के संबंध में विधिसम्मत निर्णय लेने का भी निर्देश दिया। इसके बावजूद लंबे समय तक जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एडo होता ने २२ मार्च २०२५ को प्रधान मंत्री कार्यालय को इसकी सूचना दी। प्रधान मंत्री कार्यालय ने ६ अप्रैल को राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री कार्यालय को निर्देश दिया। पहली बार वे २१ मई को जंतर–मंतर पर धरने पर बैठे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष जी को ज्ञापन सौंपा। लेकिन, विद्यातत्त्वम् पद्धति को अभी तक **NEP** में शामिल नहीं किया गया है। इस बीच, **NCERT** के अध्यक्ष को सदानन्द तत्त्वज्ञान परिषद् के तरफ से २३ जुलाई २०२५ को विद्यातत्त्वम् पद्धति से संबंधित सभी दस्तावेज सौंप दिए गए और १३ अगस्त को संस्था के तरफ से हजारों भक्त सेवक लोगों ने जंतर मंतर में शांति पूर्ण प्रदर्शन करते हुए आंदोलन को जारी रखा। उक्त प्रदर्शन के बीच महात्मा शिवानन्द ने कहा मानव जीवन धरती में सबसे खुशहाल जीवन होना रहना चाहिए परन्तु ज्ञान के अभाव में मानव जीवन को पशु से भी बदतर जीवन बना कर विषय भोग में लगा दिया गया जिसके कारण से समाज में स्वार्थ और पतन चरम पर है । समाज में हत्या, हिंसा, चोरी, बेइमानी, लूट, खसोट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, भेदभाव, सांप्रदायिकता आदि व्याप्त हो गया। अब अगर समाज को दोष दुर्गुण रहित परमार्थी बनाना है तो समाज में विद्या तत्त्वम पद्धति को लागू करना ही होगा। धरना प्रदर्शन के पश्चात प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को संस्था के तरफ से ज्ञापन सौंपा गया है।

अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा में गए किसानों ने दिया १३ सूत्री मांग पत्र

मोहम्मदी खीरी। किसान संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों ने ३० किलोमीटर की लंबी दूरी तय करते हुए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। रास्ते में किसानों का जगह–जगह स्वागत किया गया उत्साह से लेबरेज किसानों की यात्रा मोहम्मदी मंडी परिसर में पहुंचने पर स्थानीय गया और स्थानीय किसान कारवां में शामिल होते रहे जिससे उनकी संख्या बढ़ती चली गई मोहम्मदी मंडी परिसर में पहुंचने पर किसानों ने स्वागत किया है। किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित अपनी १३ सूत्री मांगों का मांग पत्र एसडीएम की अनुपस्थिति में तहसीलदार लेने पहुंचे जहां किसानों ने उन पर खाद की किल्लत को लेकर कई

किसानों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह–जगह पुलिस बल तैनात किया गया उनकी मांगों का ज्ञापन लेने पहुंचे तहसीलदार संतुष्ट न कर पाने पर वापस बैरंग लौट गए जिससे गुस्साए किसान धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे जिससे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर गोला से मोहम्मदी की तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए जिनका जगह–जगह पर स्वागत किया सवाल दाग दिए जिससे वह निउत्तर हो गए किसानों ने समस्या को निर्धारित समय में हल करने का आश्वासन मांगा जिस पर तहसीलदार खींज कर चले जाने से हमारी मांगे पूरी करो कह कर हंगामा काटने लगे। तहसीलदार से वार्ता विफल होने पर सीओ अरुण कुमार सिंह और निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने संभाला मोर्चा किसानों से वार्ता विफल होने पर पुलिस के अधिकारी सामने आए उन्होंने किसानों की समस्या के लिए उच्च अधिकारियों से वार्ता कर किसानों का प्रतिनिधिमंडल डीएम खीरी से मिलने की वार्ता कराई यूरिया की मांग ५ दिन के भीतर सुनिश्चित कराने काआश्वासन देने पर सहमत बनी। किसानों ने दिया १३ सूत्री मांग पत्र मांग पत्र में किसानों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो क रपोरेट खेती छोड़ो, अमेरिका द्वारा लगाए गए २५ परसेंट टैरिफ का विरोध, राष्ट्रीय सहकारी नीति का विरोध, समर्थन मूल्य की गारंटी और खरीद सुनिश्चित करना, कर्ज माफी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बंद हो, बिजली के क्षेत्र में निजीकरण और स्मार्ट मीटर का विरोध, पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग का विरोध, किसानों को १० हजार की पेंशन की मांग, पुराने ट्रैक्टर पर प्रतिबंध की नीति का विरोध, विश्व आदिवासी दिवस और मूलवासी दिवस ६ अगस्त २०२५ अमर रहे वन अधिकार अधिनियम २००६ मूल भावना में लागू किया जाए, विद्यालयों को बंद करने की नीति वापस ली जाए, पुलिस प्रशासन द्वारा समर्थित सांप्रदायिक हिंसा को रोका जाए, यूरिया खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और किसानों पर लाठियां न चलें, और बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल की तीनों यूनिटों द्वारा पिछले वर्ष का भुगतान दिलाया जाए। तिरंगा यात्रा में किसान संगठन के लोगों के साथ बलवीर सिंह मध्यांचल प्रभारी, मोनू यादव, साजिया अल्वी, मुख्तार सिंह, आकाश भारती, अमरदीप सिंह, बलजिंदर सिंह, गुरजीत सिंह, संग्राम सिंह, अचल सिंह आकाश सिंह समेत हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे।

'कलेक्ट्रेट से निकली तिरंगा बाइक रैली, डीएम-सीडीओ ने किया रवाना'

'देशभक्ति की बाइक रैली में सुरक्षा की मिसाल'

लखीमपुर खीरी। ष्हर घर तिरंगा अभियानष् के तहत बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर से पंचायती राज विभाग के अधिकारी–कर्मचारियों की तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और सीडीओ अभिषेक कुमार ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस मौके पर एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम अनिल रस्तोगी, पीडी एसएन चौरसिया, एसओसी संजय आनंद और डीपीआरओ विशाल सिंह मौजूद रहे। रैली कलेक्ट्रेट से शुरू होकर गुरु गोविंद सिंह चौक, जीआईसी, विलोबी मार्ग होते हुए वापस कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई। पूरे मार्ग पर बाइक सवार तिरंगे लहराते हुए देशभक्ति के नारे लगाते रहे। खास बात यह रही कि सभी बाइक सवार और पीछे बैठे कार्मिक हेलमेट पहने हुए थे, जिससे रैली ने देशभक्ति के साथ–साथ सड़क सुरक्षा का भी सशक्त संदेश दिया। रैली को संबोधित करते हुए डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की पहचान ही नहीं, बल्कि सम्मान, एकता और बलिदान का प्रतीक है। 'हर घर तिरंगा' केवल झंडा फहराने का नहीं, बल्कि देशभक्ति को गहराने का अवसर है। उन्होंने सभी से १३ से १५ अगस्त के बीच घर, संस्थान और कार्यस्थल पर तिरंगा लगाकर इसे जन–जन का उत्सव बनाने की अपील की। सीडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि आज की यह यात्रा केवल बाइक रैली नहीं, बल्कि देश के प्रति हमारी आस्था और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हम सभी को अपने–अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान को सफल बनाना चाहिए।

सरकार के निर्देशानुसार हर घर पर फहराया जायेगा तिरंगा।

गोला गोकर्णनाथ खीरी। उत्तर प्रदेश व भारत सरकार की मंशा अनुरूप पूरे देश मे ऐक साथ आगामी पन्द्रह अगस्त को सभी घरो मे राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा। जिसके चलते गोला ब्लाक कुम्भी गोला के सभागार मे खंड विकास अधिकारी शरद कुमार सिंह की अगुवाई मे ब्लाक कुम्भी की कुल ७४ ग्राम पंचायतो के प्रधानो को राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया। जिसके चलते प्रत्येक ग्राम प्रधान को २५० राष्ट्रीय ध्वज वितरित किये है। इस अवसर पर ब्लाक प्रमुख विमल वर्मा ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतो को सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ध्वज वितरित किये गये है जो खिलाफ पूरे भारत देश मे हर घर तिरंगा लहराया जायेगा।इस अवसर पर लाल्हापुर ग्राम प्रधान जनार्दन गिरि व उनके अनुज धर्मेन्द्र गिरि मोंटी ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिये सभी ग्राम प्रधानो को प्रेरित किया है।उक्त अवसर पर ऐडीओ पंचायत अवनीश कुमार त्रिपाठी ने सभी प्रथानो से कहा कि सरकार के इस बडे आयोजन मे हम सभी का सहयोग रहेगा और आप सभी लोगो के सहयोग से विश्व रिक र्ड बनेगा।

पीड़ित पत्रकारों ने लगाई सीएम से न्याय के गुहार

अस्पताल में ड्यूटी पर सो रहे ड क्टर और पैरा स्टाफ का वीडियो बनाने से बौखलाए अस्पताल कर्मियों ने मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया और फर्जी आरोप लगाकर चौकी प्रभारी से सांठगांठ कर किया खेल लिखवाया गया फर्जी मुकदमा।

लखीमपुर खीरी । मामला जिला चिकित्सालय मोतीपुर का है जहां डॉक्टर और पैरा स्टाफ द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और वसूली तथा लापरवाही का चल रहे खेल की चर्चा आम बनी हुई है। यह अस्पताल हमेशा अपनी काली करतूतों के लिए चर्चा में बना हुआ है। मामला चाहे वह बाहर से भारी कमीशन वाली दवाई मरीजों को लिखे जाने का हो या फिर चिकित्सा अधीक्षक द्वारा ड्यूटी के दौरान अपने साथियों के साथ अधीक्षक के कमरे में शराब और मीठ का आनंद लिया जाना हो या फिर अपने द्वारा अपने चहेते डॉक्टरों द्वारा रखे गए प्राइवेट लड़कों से अ परेशन के नाम पर ४००० से ६००० रुपए की वसूली किए जाने का मामला हो। यह अस्पताल अक्सर अखबारी सुर्खियों में रहने वाला जिला अस्पताल है। इतना ही नहीं जिला अस्पताल में जब से आर के कोली साहब सीएमएस हुए हैं तब से अस्पताल भ्रष्टाचार और दलालों का अड्डा बनकर रह गया है। यह मेरा नहीं बल्कि ओयल अस्पताल से आने वाले दर्जनों लोगों का आरोप है। सूत्र द्वारा इसी तरह की मिली जानकारी तो स्वतंत्र प्रभात संवाददाता शमशेर अपने एक पत्रकार साथी जो पवन वेग समाचार पत्र और पीवी २४ न्यूज चौनल के सह संपादक विशाल भारद्वाज है जिनके साथ खबर कवरेज करने दिनांक ११ ८.२०२५ को जिला अस्पताल गए और तीसरी मंजिल के वार्ड के डॉक्टर और पैरा स्टाफ सोते दिखाई पड़े तो पत्रकारों ने इसे अपने कमरे में कैद कर लिया। अपनी गर्दन फसाते देख उक्त डॉक्टर और पैरा स्टाफ ने अपने पूरे स्टाफ के साथ दोनों पत्रकारों को बंधक बना लिया और दोनों के मोबाइल छीन लिए। सभी फोटो वीडियो डिलीट कर दिए और आमादा फौजदारी हो गये। अपने को घिरता देख संवाददाता ने अपने साथियों को बताया तो मौके पर पहुंचे नित्यानंद बाजपेई और मनोज मिश्रा ने मामले की जानकारी ली और मोबाइल वापस दिलाया मामले की गंभीरता और मीडिया में अपने को घिरता देख अस्पताल के तत्कालीन अधीक्षक जो गत दस वर्षों से लगभग जिला अस्पताल में जमे हैं। जिनके द्वारा पुलिस को मैनेज करके दारू पीकर हंगामा और महिला स्टाफ से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए चालान भिजवा दिया। पत्रकार अपना आईडी कार्ड और अथ रिटी लेटर दिखाते रहे। और मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की मांग करते रहे। लेकिन पुलिस अस्पताल कर्मियों की ताल पर थिरकती हुए। बिना जांच किए ही चारों पत्रकारों का चालान भेजने में मशगूल रही। पत्रकारों ने मामले की लिखित शिकायत डीएम खीरी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सहित मंडलाआयुक्त लखनऊ मंडल लखनऊ तथा भारतीय प्रेस परिषद नई दिल्ली को भेज कर मामले की उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर निष्पक्ष जांच कराए जाने तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

सेहत महकमा को बेनकाब करने का इनाम चालान

लखीमपुर खीरी । जिला खीरी में चल रही अफसर शाही की तानाशाह रवैया की एक ऐसी मिसाल सामने आई जिसने सूबे के मुखिया के सभी दावों और वादों की हवा निकाल दी और जनपद में नौकरशाही के आगे अफसर शाही की कोई अहमियत नहीं है । जिले में सिर चढ़कर बोल रही नौकरशाही के चलते लोगों का विश्वास वर्तमान सरकार से उठता जा रहा है।और सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ जरूरतमंद गरीब तबके के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है।भले ही उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार द्वारा गरीब मजलूमों वंचित तबके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करने को लेकर पानी जैसा पैसा बहाया जा रहा हो पर यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर रह जाता है। और गरीब सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पताल की तरह पैसा खर्च करने के बाद भी सरकारी अस्पतालों में इलाज करने को विवस है। ताजा मामला जनपद खीरी के जिला अस्पताल ओयल मोतीपुर का है। जहां पर जिला अस्पताल के मरीजों को धड़ल्ले से दुगनी एमआरपी वाली महंगी कमीशन वाली दवाइयां बाहर से मेडिकल स्टोर से लिखी जा रही है। सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि अ परेशन के नाम पर ४००० से लेकर ६००० रूपया तक सर्जन लोगों द्वारा अपने प्राइवेट लड़कों द्वारा वसूल करने के बाद ही अ परेशन किया जाता है। इतना ही नहीं गति महा पूर्व एक मरीज से टांका लगाने वाला धागा तक यह कहते हुए मंगवाया गया कि यहां धागा अच्छा नहीं है। अधि ाकांश अ परेशन के समय बाहर से दवाएं मरीज को खरीदनी पड़ती है। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक और पैथोल जी से लेकर अल्ट्रासाउंड सेंटर तक दलालों और चंद आशाओं के माध्यम से जांच के नाम पर वसूली होने का खेल चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला दिनांक १०, ८.२०२५ की रात समय लगभग १ बजे का होगा जब पत्रकार शमशेर अपने एक साथी विशाल भारद्वाज के साथ जिला अस्पताल अपने एक मरीज जिला अस्पताल में आने की सूचना पर गए। और मरीज का पता किया तो पता चला कि मरीज नहीं आया है। वहीं पर उक्त लोगों को एक जानकारी विभागीय सूत्रों द्वारा ही मिली तीन मंजिल वार्ड में सभी ड्यूटी पर लगे स्थाई कर्मी खर्राटे मार रहे हैं और मरीज दर्द से कराह रहा है। उक्त सूचना पर गए दोनों पत्रकारों द्वारा उक्त मामले का वीडियो कैमरे में कैद कर लिया गया। वार्ड के पास बैठा गार्ड भी बैठे–बैठे नींद का लुत्फ ले रहा था। इसकी भनक जब अस्पताल कर्मियों को लगी तो वहां पर आए अस्पताल कर्मी वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाने लगे और पत्रकारों द्वारा ऐसा करने से मना करने पर उक्त लोगों द्वारा मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट कर दिया गया। इसकी सूचना पत्रकार ने अपने साथियों को दी तो मौके पर पहुंचे पत्रकार नित्यानंद वाजपेई वह मनोज मिश्रा ने मामले की जानकारी ली तब उग्र होकर अस्पताल कर्मियों द्वारा फर्जी आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीत कराकर मामले को दबाने का प्रयास करने लगे इस तरह से सच्चाई को सामज में आईना करना पत्रकारों को भारी पड़ गया। पुलिस द्वारा उन्ही डॉक्टर से शराब पीने पुष्टि की जांच कराई गई जब वही वादी मुकदमा वहीं डॉक्टर तो जांच में जो चाहे वो लिख दे। यदि मामले की कराई जाए निष्पक्ष जांच और ईमानदारी से खागाले जाएं सभी वार्डों के सीसीटीवी फुटेज तो होगा दूध का दूध पानी का पानी सीसीटीवी कैमरा ही बताएगा कि कौन था और किसने छेड़छाड़ की तो सच आ जाएगा सामने। मामले की आरटीआई से सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई है। लोगों की जुबानी सत्य माने तो रात को ५० रुपए में मिलने वाला इंजेक्शन खरीदवाया जाता है। यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। एक ड क्टर २० साल से एक ही जगह जमा हुआ है क्या यह स्थानान्तरण नीति की अवमानना नहीं है। इन सबको शासन के समक्ष लाना अपराध है और भ्रष्टाचार का खुलासा करना अपराध है तो हमने यह अपराध किया है।

'दुकानों पर ओवर रेट पर बिक रही देशी शराब' 'अबकारी अधिकारी जानकारी होने के बाद भी नहीं करते कार्रवाई'

'पलियाकलां –खीरी। मझगई कस्बे में चौखड़ा रोड पर संचालित शराब की दुकान, जहां हो रही मनमानी के चलते देशी शराब को सरकारी रेट पर न बेच कर ओवर रेट बेचा जा रहा है। यह कार्य शराब दुकान मालिक आबकारी विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर कर रहे हैं। जिसकी वजह से आए दिन सेल्समैन और ग्राहक के बीच दुकानों पर झगड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि अंग्रेजी हो या फिर देसी शराब दुकान सभी दुकानों में प्रिंट रेट से दस से बीस रुपए अधिक दर पर बेची जा रही है, साथ ही शराब की दुकानों पर रेट लिस्ट भी नहीं लगी है। वहीं शराब की मिल रही शिकायत के बावजूद पुलिस–प्रशासन व आबकारी विभाग कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मझगई निवासी पप्पू का कहना है कि शनिवार १२ बजे को बाजार में एक शराब दुकान से एक वेंडीज फ्यूटी ली तो सेल्समैन द्वारा प्रिंट रेट से अधिक १० रुपए अतिरिक्त लिए विरोध करने पर वह झगड़ा करने लगा। इसके अलावा पास के राम खिलावन् का कहना है कि कस्बे में संचालित देशी शराब

दुकानों पर जमकर ओवर रेट में शराब बेची जा रही है। यह सब अबकारी विभाग के अधिकारियों की जानकारी में हो रहा है। इस कारण से वे शराब दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शराब पीने वाले लोग यह सब जानते हैं, लेकिन झगड़े के डर के कारण यह लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते और विरोध किए बिना ही शराब खरीदकर चलते जाते हैं।

राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्राधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन।

गोला गोकर्णनाथ खीरी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष राकेश कनौजिया के साथ सैकड़ो कार्यकर्ताओं ने गोला कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय लखीमपुर को सौंपा गया। इसमें मांग की गई है कि राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष देव जुनेजा पर एक ढाबे पर हुई मारपीट में इंव ल्व किया गया है और पुलिस द्वारा संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया जो कि बेबुनियाद व निराधार और झूठा है। जबकि देव जुनेजा द्वारा कोई झगड़ा नहीं हुआ जिन लोगों में झगड़ा हुआ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देव जुनेजा को बेवजह झूंठे मुकदमे में फसाया जा रहा है। जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि मामले की सक्षम अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाए। और संगठन के कार्यकर्ता पर लगे झूठे मुकदमे को हटाया जाए। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में बताया है कि देव जुनेजा जी को न्याय नहीं मिला तो राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हर जिले में एक बड़ा आंदोलन होगा जिसका शासन प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। जिसके लिए संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को अगर जेल भी जाना पड़े तो जेल जाने के लिए तैयार है। ज्ञापन सोते समय जिला अध्यक्ष कनौजिया के साथ जिला महामंत्री प्रदीप जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष अनुज वर्मा,जिला मीडिया प्रभारी पंकज शुक्ला,जिला संयोजक ठाकुर पंकज सिंह, जिला मंत्री अखिलेश जायसवाल, आकाश बजरंगी, राहुल शर्मा,शिवम श्रीवास्तव, पारुस श्रीवास्तव, मनोज वर्मा, जितेंद्र कुमार,विकास कनौजिया, गगन कुमार,सोनू कुमार, प्रमोद गुप्ता,अशोक जायसवाल, अंशुल जायसवाल, सर्वेश कुमार, पवन कुमार,विक्रम सिंह, संजय सिंह चौहान,राजीव कुमार, विनोद कुमार, सुनील बाजपेई, अंशु वर्मा सहित सैकड़ो कार्यकर्ता मौजूद रहे।

'कस्बा प्रभारी बाबूराम का गैर जनपद स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह हुआ।'

'मोहम्मदी खीरी कस्बा प्रभारी बाबूराम का गैर जनपद स्थानांतरण होने पर विदाई दी गई कस्बा प्रभारी बाबूराम लगभग दो वर्षों से कस्बा चौकी पर तैनात थे। इस दौरान उनका क्षेत्र के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रहा। जब स्थानीय लोगों को उनके स्थानांतरण की जानकारी मिली, तो बड़ी संख्या में लोग फूल मालाएं लेकर उनसे मिलने पहुंचे।विदाई समारोह के दौरान समस्त चौकी स्टाफ की आंखें नम दिखीं। उनकी कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए सभी ने फूल मालाएं पहनाकर उन्हें विदा किया और उनकी तरक्की की शुभकामनाएं दीं। इस मौके पर समस्त चौकी स्टाफ सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे।'

मेरी जान को खतरा है..., राहुल गांधी ने पुणे कोर्ट में क्यों डाली अर्जी, महात्मा गांधी की भी हत्या का है जिक्र

लखनऊ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि कुछ भाजपा सांसदों ने उन्हें धमकी दी है कि २०२२ में श्भारत जोड़ो यात्राश के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए उनका भी वही हश्र होगा जो उनकी दादी पूर्व प्रध ानमंत्री इंदिरा गांधी का हुआ था। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को पुणे की एक अदालत को सूचित किया कि उनके हालिया राजनीतिक संघर्षों और उनके खिलाफ मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर के वंश को देखते हुए उन्हें जान का खतरा है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने मानहानि के एक मामले की सुनवाई कर रही विशेष सांसदधविधायक अदालत से आग्रह किया कि वह उनकी सुरक्षा और मामले की निष्पक्षता को लेकर उनके द्वारा व्यक्त की गई गंभीर आशंकाओं का न्यायिक संज्ञान ले। सत्यकी सावरकर ने एलओपी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जब उन्होंने मार्च २०२३ में लंदन में एक भाषण दिया था। इस भाषण में सावरकर के लेखों में एक घटना का जिक्र था जिसमें सावरकर और अन्य लोगों ने कथित तौर पर एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया था और इसे 'सुखद'

पाया था। कांग्रेस नेता की ओर से पुणे की अदालत में अर्जी दाखिल करने वाले वकील मिलिंद पवार ने इस बात पर जोर दिया कि भाजपा नेता आरएन बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा है। उन्होंने कथित तौर पर यह भी बताया कि भाजपा नेता तरविंदर मारवाह ने भी राहुल गांधी को खुली धमकी देते हुए कहा था कि उन्हें 'अच्छा व्यवहार करना चाहिए, वरना उनकी दादी जैसी ही हालत हो सकती है।' गांधी के आवेदन में आगे लिखा है, षशिकायतकर्ता ने स्वयं महात्मा गांधी के हत्यारों के सहयोगियों से अपनी वंशावली का दावा किया है। इस वंश से जुड़े गंभीर इतिहास को देखते हुए, बचाव पक्ष को वास्तविक और उचित आशंका है कि इतिहास को खुद को दोहराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि शिकायतकर्ता के वैचारिक पूर्वजों द्वारा अपनाई गई हिंदुत्व की विचारधारा ने कई मामलों में असंवैध ानिक तरीकों से राजनीतिक सत्ता हासिल की है।' सत्यकी सावरकर ने सावरकर की प्रकाशित रचनाओं में इस तरह के विवरण के अस्तित्व पर विवाद किया और अदालत का रुख करते हुए तर्क दिया कि ये टिप्पणियाँ झूठी, भ्रामक और मानहानिकारक थीं। उन्होंने गांधी को आईपीसी की धारा ५०० के तहत दोषी ठहराए जाने और सीआरपीसी की धारा ३५७ के तहत मुआवजे की मांग की है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई १० सितंबर को करेगी।

पहले ७ पेपर थे, अब तो ११ में कोई एक कागज मांगे रहे, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR को वोटर फ्रेंडली बताया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को 'मतदाता–अनुकूल' बताया और स्वीकार्य पहचान दस्तावेजों की संख्या में विस्तार पर जोर दिया और आध ार को शामिल न करने की चिंताओं को खारिज कर दिया। अदालत ने यह भी जाँच की कि क्या वैधानिक प्रपत्र को समाहित करने वाले गणना प्रपत्र को विरोधाभासी या अधिक समावेशी माना जा सकता है। पीठ ने पूछा कि यदि कोई गणना प्रपत्र वैध ानिक प्रपत्र को अपने दायरे में ले लेता है, तो क्या यह उल्लंघन होगा या अधिक समावेशी अनुपालन होगा? याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर नागरिकता प्रमाण पर अपना रुख पलटने का आरोप लगाया। सिंघवी ने कहा कि ईसीआई नागरिकता प्रमाण पर पूरी तरह से पलट गया है। किसी को आपत्तिकर्ता बनना होगा और कहना होगा कि अमुक व्यक्ति नागरिक नहीं है। फिर ईआरओ नोटिस जारी करता है और मुझे जवाब देने का समय देता है। आप दो महीने में सारे व्यापक न्यायिक कार्य कैसे कर पाएँगे? दिसंबर से एसआईआर करें और पूरा एक साल लग जाए, कोई भी इसके खिलाफ नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि फॉर्म ६ के तहत भी, आधार

नामांकन के लिए एक वैध दस्तावेज बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इस धारणा को पूरी तरह से उलट दिया है। वे कहते हैं कि जब तक आप कुछ और साबित नहीं कर सकते, तब तक आप सभी को बाहर रखा जाएगा।' उन्होंने चेतावनी दी कि '२००३–२०२५ के बाद नामांकित सभी लोगों को, जब तक वे साबित नहीं कर सकते, तब तक बाहर रखा जाएगा।

जब गुप्त मतदान से चुनाव होंगे तो तथाकथित चाणक्य पूरी तरह हार जाएंगे, कपिल सिब्बल का अमित शाह पर तंज

नई दिल्ली। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने बुध ावार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने हाल ही में संपन्न कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया (**CCI**) के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद राजीव प्रताप रूडी की जीत को लेकर शाह पर तंज कसा। उन्होंने **X** पर पोस्ट किया कि जब चुनाव गुप्त मतदान से होते हैं, तो तथाकथित चाणक्य आसानी से हार जाते हैं। बिहार में, अगर चुनाव निष्पक्ष होता है, तो चाणक्य फिर से हार जाएँगे। रूडी ने २५ साल की सत्ता विरोधी लहर का सामना करने के बावजूद, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब अ फ इंडिया के सचिव (प्रशासन) के रूप में अपना पद बरकरार रखा और अपने साथी पार्टी सदस्य संजीव बालियान को हराया, जिन्हें केवल २६० वोट मिले। जश्न के बीच, भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपनी जीत का श्रेय अपने पैनल को दिया और कहा कि मैं शायद १०० से ज्यादा वोटों से जीता हूँ। और अगर इसे १००० मतदाताओं से गुणा किया जाए, तो यह संख्या १ लाख हो जाती है। यह मेरे पैनल की जीत है। सभी ने अपनी पार्टी से उठकर अपना वोट डाला। मेरे पैनल में कांग्रेस, सपा, टीएमसी और निर्दलीय सांसद शामिल थे। मुझे पिछले दो दशकों के अपने प्रयासों का फल मिला। यह ऐसे समय में

हुआ है जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे सचिव पद में बदलाव की उम्मीद कर रहे थे और स्पष्ट रूप से बाल्यान को क न्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में जीत दिलाना चाहते थे। निशिकांत दुबे ने पहले संवाददाताओं से कहा था, 'मुझे लगता है कि बदलाव होगा और डॉ. संजीव बाल्यान नए सचिव होंगे... राजीव प्रताप रूडी मेरे पुराने मित्र हैं।' ११ सदस्यीय निकाय के आंकड़ों से पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनावों में विपक्ष का दबदबा है, और ज्यादातर पदों पर इंडिया ब्लॉक के सदस्यों का कब्जा है। इस चुनाव में, कांग्रेस और अन्य इंडिया ब्लॉक दलों के प्रमुख नेता संजीव बाल्यान के खिलाफ रूडी के पैनल का हिस्सा थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) सांसद तिरुचि शिवा निर्विरोध सांस्कृतिक सचिव चुने गए हैं, उनके बाद कांग्रेस के राजीव शुक्ला खेल सचिव और कांग्रेस के जितेंद्र रेड्डी निर्विरोध कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। इसके अलावा, कांग्रेस सांसद देवेंद्र सिंह हुड्डा और समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद अक्षय यादव ने भी भाजपा के नवीन जिंदल और प्रदीप गांधी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की गवर्निंग काउंसिल में स्थान हासिल किया है। गौरतलब है कि रूडी को रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के सांसद एनके प्रेमचंद्रन का समर्थन प्राप्त था, जो चुनाव में विजयी हुए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनावों में सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दलों के शीर्ष नेताओं ने अपने वोट डाले।

विकास कार्य करते समय पर्यावरण की रक्षा करना जरूरीः उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को तेलंगाना सरकार को कांचा गाचीबोवली वन स्थल के समग्र पुनरुद्धार के वास्ते एक ''अच्छा प्रस्ताव'' पेश करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया और कहा कि राज्य सरकार को काटे गए पेड़ों को फिर से लगाना होगा। प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि वन क्षेत्र को बहाल किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए। पीठ ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह बाद के लिए स्थगित करते हुए कहा, समय–समय पर न्यायालय कहता रहा है कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन यह सतत विकास होना चाहिए। विकास संबंधी गतिविधियां करते समय, पर्यावरण और वन्य जीवन के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए तथा क्षतिपूर्ति के उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए। यदि सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर आती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। तेलंगाना सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार पूरे प्रस्ताव पर समग्र रूप से विचार कर रही है, जिसमें पर्यावरण और वन्यजीवों के हितों को विकास कार्यों के साथ संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने १५ मई को कहा था कि हैदराबाद विश्वविद्यालय के निकट पेड़ों की कटाई प्रथम दृष्टया पूर्व नियोजित प्रतीत होती है। अदालत ने तेलंगाना सरकार से कहा था कि वह इसे बहाल करे अन्यथा उसके अधिकारियों को जेल हो सकती है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि यह सरकार पर निर्भर है कि वह जंगल को बहाल करे या अपने अधि ाकारियों को जेल भेजे। कांचा गाचीबोवली वनक्षेत्र में वनों की कटाई की गतिविधियों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए, उच्चतम न्यायालय ने तीन अप्रैल को अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। न्यायालय ने पेड़ों की कटाई के लिए जल्दबाजी में की गई कार्रवाई के लिए १६ अप्रैल को तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई थी और निर्देश दिया था कि यदि वह चाहती है कि उसके मुख्य सचिव को किसी भी गंभीर कार्रवाई से बचाया जाए, तो उसे १०० एकड़ वन–रहित भूमि को बहाल करने के लिए एक विशिष्ट योजना प्रस्तुत करनी होगी।

घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के आरोप में उत्तर प्रदेश के रियल्टी समूह के खिलाफ ईडी ने छापे मारे

लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निवेशकों से २४८ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में धनशोधन की जांच के तहत उत्तर प्रदेश स्थित एक रियल्टी समूह के खिलाफ बुधवार को छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि 'रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड' के खिलाफ मामले में लखनऊ में कम से कम आठ और दिल्ली में दो परिसरों पर छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है। धन शोधन का यह मामला २०२१ से घरध्व्यावसायिक स्थान खरीदने वालों द्वारा दर्ज कराई गई ८७ प्राथमिकियों से जुड़ा है। इन प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया है कि खरीदारों के साथ ध ोखाधड़ी की गई और उन्हें उनकी संपत्तियां नहीं दी गईं। सूत्रों ने बताया कि 'यूपी रेरा' (उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण) द्वारा किए गए फोरेंसिक ऑडिट के अनुसार, इस मामले में ''अपराध से अर्जित आय'' २४८ करोड़ रुपये है। उन्होंने दावा किया कि सबूत जुटाने और प्रवर्तकों की संपत्ति जब्त करने के उद्देश्य से यह छापेमारी की जा रही है क्योंकि वे पिछले चार वर्षों से ''फरार'' हैं। कंपनी के प्रवर्तकों की पहचान पीयूष रस्तोगी, परेश रस्तोगी और दीपक रस्तोगी के रूप में की गई है।

यूपी विधानसभा में पास हुआ बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन श्बांके बिहारी मंदिर न्यास विधेयक पेश किया गया और पारित कर दिया गया। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक मंदिर के प्रबंधन को संस्थागत रूप देना और उसकी सदियों पुरानी परंपराओं को संरक्षित करना है। सरकार का कहना है कि नया न्यास संत–स्वामी हरिदास द्वारा स्थापित परंपराओं की रक्षा करते हुए श्रद्धालुओं के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएँ सुनिश्चित करेगा। विध ोयक के अलावा, १३ अगस्त को सुबह ११ बजे श्विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेशश विजन डॉक्यूमेंट २०४७ पर २४ घंटे की चर्चा शुरू हुई, जिसमें सरकार विभागीय उपलब्धियों और विजन योजनाओं का विवरण प्रस्तुत कर रही है, जबकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। मंदिर परिसर में मूर्तियाँ और संपत्ति, देवताओं को दिए गए उपहार और चढ़ावे, किसी भी अनुष्ठान, समारोह, धार्मिक आयोजनों के लिए दी गई

संपत्तियाँ, मौद्रिक दान– चाहे नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, या डाक या टेलीग्राफ द्वारा भेजा गया हो, संक्षेप में, श्री बांके बिहारी जी मंदिर की सभी चल–अचल संपत्तियाँ, ट्रस्ट के प्रबंधन के अधीन मानी जाएँगी। विधेयक इस बात पर जोर देता है कि इस ट्रस्ट का गठन स्वामी हरिदास द्वारा शुरू की गई परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है, जिन्हें मंदिर की भक्ति परंपराओं की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। सभी रीति–रिवाज, त्योहार और अनुष्ठान बिना किसी हस्तक्षेप या बदलाव के जारी रहेंगे। एक बार गठन हो जाने पर, बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट तीर्थयात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएँ विकसित करेगा, जैसे–व्यवस्थित प्रसाद वितरण, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए अलग दर्शन मार्ग, पेयजल सुविधाएँ, आराम के लिए बेंच, आसान पहुँच और कतार प्रबंधन कियोस्क, गौशालाएँ, सामुदायिक भोजन कक्ष (अन्नक्षेत्र), विशाल रसोईघर, होटल, गेस्टहाउस, प्रदर्शनी हॉल, रेस्टोरेंट और प्रतीक्षालय, ट्रस्ट में ११ मनोनीत सदस्य और ७ पदेन सदस्य होंगे।

दिल्ली के गीता कॉलोनी में पैसों के लेन–देन को लेकर एक व्यक्ति पर गोलियां चलायी गईं

नई दिल्ली। दिल्ली के गीता क लोनी इलाके में पैसों के लेन–देन को लेकर हुए झगड़े के बाद तीन लोगों ने २५ वर्षीय एक युवक पर कथित तौर पर गोलियां चलायीं। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना मंगलवार रात करीब १०रू३० बजे ताज एन्क्लेव के पास हुई। पुलिस उपायुक्त (शाहदरा) प्रशांत गौतम ने बताया कि जगतपुरी निवासी शिकायतकर्ता शिवम शर्मा ने पुलिस को बताया कि उसने कुंदन नगर में रहने वाले एक दंपति को पैसे उधार दिए थे। बार–बार मांगने के बावजूद, शीतल और उसके पति सोनू ने पैसे वापस नहीं किए। उन्होंने बताया कि मंगलवार तड़के जगतपुरी लाल बत्ती के पास शर्मा की दंपति के साथ तीखी बहस हुई और बाद में जब वह अपने दोस्त जतिन नागपाल के साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए ताज एन्क्लेव गए, तो तीन लोगों शादाब, हर्षु और रमन ने उन्हें रोका और उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। झगड़े के दौरान शादाब ने कथित तौर पर एक बन्दूक निकाली और शर्मा पर दो गोलियां चलाईं। पुलिस उपायुक्त ने कहा, ''गोली चलने के दौरान शिकायतकर्ता किसी तरह सुरक्षित बच निकला।'' पुलिस के अनुसार, गीता क लोनी थाने में हत्या के प्रयास और शस्त्र कानून से संबंधित बीएनएस ध ाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने बताया कि शर्मा के खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता की धारा ३०७ (हत्या का प्रयास) के तहत पहले एक मामला दर्ज है। मामले की जांच जारी है।

चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव करने पहुंचे NSUI कार्यकर्ता

लखनऊ। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (**NSUI**) की तरफ से बुधवार को लखनऊ में प्रदर्शन किया गया है। एनएसयूआई की तरफ से किये गये इस जोरदार प्रदर्शन से हजरतगंज स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर माहौल तनावपूर्ण रहा। पुलिस की बैरिकेडिंग

तोड़कर कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के कार्यालय का घेराव किया है। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं की पुलिस से जमकर धक्का मुक्की हुई है। इसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बाद में सभी को बस से ईको गार्डेन ले जाया गया है।

हलांकि एनएसयूआई की तरफ से किये जाने वाले इस प्रदर्शन की जानकारी पहले से ही प्रशासन को हो गई थी। यही वजह है कि प्रशासन ने पहले से ही इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था, बैरिकेडिंग के साथ ही मौके पर पुलिस बल के साथ ही आरपीएफ और पीएसी के जवान तैनात किया गये थे। दरअसल, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (**NSUI**) ने यह प्रदर्शन चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ किया है। एनएसयूआई ने चुनाव आयोग को केंद्र सरकार के हाथ की कठपुतली बताते हुये जमकर नारेबाजी की। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष अनस रहमान ने कहा कि सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को दिल्ली में एक मार्च निकालने का फैसला किया था, उन्होंने बताया कि देश में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों और बिहार में **SIR** के मुद्दे पर यह फैलसा लिया गया था जैसे ही इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद से भारत निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक मार्च का फैसला किया, उन्हें पुलिस ने रोक लिया और हिरासत में ले लिया। अनस रहमान ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि यह समय संविधान बचाने का है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना चाहिए।

त्योहारों पर सख्त सुरक्षा के निर्देश

अमेठी। एडीजी जोन लखनऊ सुजीत पांडेय ने बुधवार को अमेठी पहुंचकर त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सु ढ़ करने और अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने बीट पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने तथा साइबर अपराधों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए। पुलिस कार्यालय गौरीगंज में आयोजित कार्यक्रम में आईजी रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार, जिलाधिकारी स्तर की उपस्थिति नहीं होने के बावजूद एसपी अपर्णा रजत कौशिक व एएसपी शैलेन्द्र सिंह ने एडीजी का बुके देकर स्वागत किया और उन्हें गार्ड ऑफ अ नर दिया। बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारियों व वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद एडीजी ने कहा कि आने वाले प्रमुख पर्व–चेहल्लुम, स्वतंत्रता दिवस और श्रीकृष्ण जन्माष्टमींके दौरान विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि बड़े अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर कानून के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और अपराध से अर्जित संपत्तियों का चिन्हांकन कर कुर्की की कार्यवाही की जाए। प्रारम्भिक स्तर पर अपराध नियंत्रण के लिए बीट पुलिसिंग को मजबूत कर अपराधों को जड़ से नियंत्रित करने

के निर्देश भी दिए गए। एडीजी ने वहीं कहा कि वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर कानूनी और तकनीकी दोनों तरह से नियंत्रण आवश्यक है और जनता को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को अपराधियों के प्रति "जीरो टॉलरेंस" नीति अपनाने का भी भरोसा दिलाया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में एडीजी ने बताया कि अमेठी में पिछले कुछ समय में अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाइयां हुई हैं, गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रॉपर्टी सीज की कार्रवाई की जा चुकी है और कई पुरानी मामलों का भी समाधान निकाला गया है। अधिकारियों ने बताया कि एडीजी के निर्देशों को शीघ्रता से लागू करने के लिए जिला स्तर पर विशेष पेट्रोलिंग शेड्यूल, बीट मानचित्र और साइबर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों व समारोह स्थलों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त रखने पर भी जोर दिया गया है।

डॉक्टर को वकील ने जड़े थप्पड़

लखनऊ। राजधानी स्थित अलीगंज सीएचसी के अधीक्षक को बुधवार के दिन एक वकील ने कई थप्पड़ जड़े हैं। जिस वकील ने डॉक्टर को थप्पड़ मारा है वह सीएचसी में ही तैनात एक नर्स का बेटा बताया जा रहा है। इस मामले में सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर ने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की है। दरअसल, सीएचसी अलीगंज में बतौर अधीक्षक तैनात डॉक्टर की वहीं पर सीनियर नर्स से कहासुनी हुई थी। जिससे नर्स की तबियत बिगड़ गई। वह वहीं भर्ती कराई गई। इसी के बाद वकील बेटा और पति सीएचसी पहुंचे। वहां अधीक्षक से कहासुनी होने के बाद थप्पड़ कांड हुआ। कई अन्य वकील भी सीएचसी पहुंच गए। फिर अलीगंज थाने और महिला पुलिस पहुंची। नर्स के वकील बेटे ने अधीक्षक के खिलाफ मां को ड्यूटी के दौरान प्रताड़ित करने की तहरीर दी है। इस मामले में एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें वकील और चिकित्सक को लोग अलग करते हुये दिखाई पड़ रहे हैं।

विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अब गुरुजी हाथ नहीं लगा पाएंगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अब गुरुजी हाथ नहीं लगा पाएंगे। मारपीट कर पढ़ाने, मुर्गा बनाने, एकांतवास में खड़ा करके दंड देने पर रोक लगा दी गई। शिक्षक, छात्र–छात्राओं को न तो शारीरिक दंड देंगे न मानसिक। ऐसा करने वाले शिक्षक कार्रवाई की जद में आएंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने ये नया नियम लागू कर दिया है। सरकारी या निजी विद्यालय, कहीं भी अब विद्यार्थियों की पिटाई नहीं की जाएगी। नई व्यवस्था के मुताबिक अगर शिक्षक किसी विद्यार्थी की पिटाई लगाते हैं या फिर मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाते हैं तो बच्चे इसका विरोध कर सकते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) को निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि विद्यालयों के साथ बाल संरक्षण गृह, छात्रावास और विद्यालयों में ऐसी व्यवस्था की जाए, जहां विद्यार्थी बेखौफ होकर अपनी बात रख सकें। अभिभावक शिक्षक

समितियां बच्चों की शिकायतों की समीक्षा करें। इसके बारे में जन–जागरुकता फैलाई जाए। जरूरी हो तो इस प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूह का भी सहयोग लिया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार (RTE) का अनुपालन हर हाल में कराया जाए। किसी भी विद्यार्थी को अब शारीरिक और मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं किसी भी विद्यार्थी के साथ जाति–धर्म, लिंग की बुनियाद पर गलत व्यवहार या भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यहां तक कि बच्चों की चिकोटी लेना, थप्पड़ जड़ना, घुटनों के बल बैठाना, छड़ी–पटरी किसी भी तरह से पिटाई नहीं करेंगे। इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए विद्यालयों के मुख्य द्वारा पर एक टोल फ्री नंबर दर्ज किया जाएगा। अभिभावक या बच्चे इस निरूशुल्क टोल फ्री नंबर १८००–८८६–३२७७ पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इन शिकायतों की नियमित म नीटरिंग होगी और इनका निस्तारण करके कार्यवाही की जाएगी।

स्वतंत्रतता दिवस पर मल्टीप्लेक्स में फ्री में दिखाई जाएगी देशभक्ति की फिल्म

लखनऊ। १५ अगस्त को स्वतंत्रतता दिवस पर राजधानी के विभिन्न मल्टीप्लेक्स में देशभक्ति पर आधारित फिल्म ''स्काई फोर्स'' का स्कूल के बच्चों और जनसामान्य के लिए निरूशुल्क प्रदर्शन किया जाएगा। यह जानकारी जिलाधिकारी विशाख जी ने दी। उन्होंने बताया कि सभी मल्टीप्लेक्स में २१५१ लोगों के बैठने की क्षमता है। वेब मल्टीप्लेक्स गोमती नगर, सिनेपोलिस बनअवध सेंटर और फन रिपब्लिक गोमती नगर, पीवीआर सहारागंज, फीनिक्स म ल आलमबाग और लूलू मॉल, आईन क्स उमराव निशातगंज, क्राउन चिनहट, एमरॉल्ड आशियाना, आइनॉक्स प्लासियो, मूवीमैक्स आलमबाग बस अड्डा, अन्तास डीडी सिनेमा गोमती नगर विस्तार और एसआरएस सिनेमा गोमती नगर में दोपहर १२ से १२रू३० के बीच शो शुरू होंगे। किसी प्रकार की जानकारी के लिए मुकुल तिवारी सहायक आयुक्त मनोरंजन कर के मोबाइल नंबर ७३७६२६७१२० एवं राज्य कर अधिकारी पीयूष कुमार यादव के मोबाइल नंबर ६४५०७३०३४५ पर संपर्क किया जा सकता है।

पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए शहर में जल्द ही नए मॉडल वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे

लखनऊ पटरी दुकानदारों को व्यवस्थित करने के लिए शहर में जल्द ही नए मॉडल वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने मंगलवार को अपर नगर आयुक्त नम्रता सिंह के साथ विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करके स्थल

चिन्हित किए। अधिकारियों ने राणा प्रताप मार्ग स्थित वेंडिंग जोन का निरीक्षण किया और इसके बाद बटलर पैलेस कॉलोनी स्थित राज्य संपत्ति विभाग के वीवीआईपी गेस्ट हाउस 'नैमिषारण्य' के पास प्रस्तावित वेंडिंग जोन की संभावनाएं देखीं। इकाना स्टेडियम के पास वेंडिंग जोन के लिए कई जगहों का निरीक्षण किया, जिनमें प्लासियो मॉल के आस–पास का क्षेत्र भी शामिल रहा। चक गंजरिया एचसीएल के पास, दयाल पैराडाइज चौराहा और जनेश्वर मिश्र पार्क के आस–पास वेंडिंग जोन स्थापित करने पर विचार हुआ। नगर आयुक्त ने सिंगापुर मॉल के पीछे सब्जी मंडी और सिनेपोलिस मॉल के पास वेंडिंग जोन बनाने के लिए स्थलों का जायजा लिया। उन्होंने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि चिन्हित मॉडल वेंडिंग जोन वाले स्थलों के टेंडर जल्द से जल्द कराके निर्माण प्रारंभ किया जाए, जिससे वेंडरों और जनता को लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान वेंडिंग जोन प्रभारी सहायक नगर आयुक्त विनीत कुमार सिंह, जोनल अधिकारी जोन एक ओपी सिंह, जोनल अधिकारी जोन ४ संजय यादव सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। नगर आयुक्त ने कहा कि इन वेंडिंग जोनों में पथ–प्रकाश, पेयजल, कूड़ा निस्तारण और यातायात व्यवस्था जैसी सुविधाएं प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि अनियंत्रित ठेला–फेरी से जहां यातायात बाधित होता है, वहीं स्वच्छता पर भी असर पड़ता है।

सोनी सब के 'उफ्फ...ये लव है मुश्किल' में क्या युग का बदलेगा मन और करेगा वह कैरी से शादी?

मुंबई। सोनी सब का लोकप्रिय शो 'उफ्फ ये लव है मुश्किल' दर्शकों को भावनाओं, ड्रामे और चौंकाने वाले मोड़ों से बांधे हुए है। इस कहानी के केंद्र में है युग सिन्हा (शब्बीर आहलूवालिया)एक ईमानदार लेकिन अंतर्मुखी वकील और कैरी शर्मा (आशी सिंह) एक जुझारू युवती जो अपने भाई–बहनों के लिए लड़ रही है और साथ ही प्यार व भरोसे की परीक्षा से गुजर रही है। हाल ही के एपिसोड्स में युग ने कैरी के भाई–बहनों को बताया कि वह उनकी सगी बहन नहीं है, जिससे कैरी टूट जाती है और उन्हें दोबारा पाने की जद्दोजहद में लग जाती है। अपने रिश्तों को वापस पाने के लिए कैरी को युग बताता है कि उसे अपने जीवन की स्थिरता और सुरक्षा साबित करनी होगी भले ही इसके लिए उसे शादी ही क्यों न करनी पड़े। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए विक्रम (रजत दहिया) एक नकली मजनूं जय (तुषार ढेम्बला) को कैरी की जिंदगी में लाकर युग और कैरी दोनों से बदला लेने की साजिश रचता है। अब कैरी मजनूं से शादी की तैयारी कर रही है, ये जाने बिना कि

उसका असली मजनूं युग ही है, दर्शकों को मिलने वाला है एक जबरदस्त ट्विस्ट। आने वाले एपिसोड्स में, जब कैरी अपने भाई–बहनों को वापस पाने के लिए शादी के लिए मंडप में बैठेगी, कुछ छिपे हुए राज और अप्रत्याशित घटनाएं पूरी कहानी को पलटकर रख देंगी। मंडप पर होगा भावनाओं से भरा टकराव, जब युग जय की असलियत उजागर करेगा और कैरी को गलत इंसान से शादी करने से रोकने के लिए दौड़ पड़ेगा। लेकिन इसी हंगामे के बीच, युग के व्यवहार में दिखेगा एक जबरदस्त बदलाव। वही युग जिसने कभी स्त्रियों से नफरत की थी, जिसने अपने दिल के चारों ओर दीवारें खड़ी कर ली थीं, और जिसने कभी प्यार न करने की कसम खाई थी अब वही युग कैरी के लिए लड़ रहा है, सच्चाई सामने ला रहा है और उसके साथ खड़ा है जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या युग का दिल सचमुच बदल गया है? क्या एक ऐसा आदमी, जो औरतों को नापसंद करता था, अब प्यार को अपना रहा है? उफ्फ ये लव है मुश्किल में कैरी का किरदार निभा रहीं आशी सिंह ने कहा, "यह ट्रैक कैरी के लिए एक भावनात्मक मोड़ है। अपने भाई–बहनों को वापस पाने की उसकी बेचैनी उसे धोखे और दिल टूटने की राह पर ले जाती है। इन एपिसोड्स की शूटिंग करना बहुत भावुक और गहरा अनुभव था, क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे प्यार और भरोसा अप्रत्याशित तरीकों से परखा जा सकता है। साथ ही, शादी वाले सीक्वेंस में सजने–संवरने का मौका मिला, जिससे गंभीर ट्रैक में एक हल्कापन और रोमांच भी जुड़ गया, और यह अनुभव और भी खास बन गया।" देखते रहिए 'उफ्फ ये लव है मुश्किल', हर सोमवार से शनिवार रात ८:०० बजे, सिर्फ सोनी सब पर।

हमारे अन्य प्रतिनिधि

lt; ckt ibl

lhrkiqj

ek-9935160370

प्रियंका त्रिपाठी

नई दिल्ली

विधिक सलाहकार

lj'k ukjk;.k feJ

क्षेत्रीय सम्पादक

lkjHk dqekj] fcgkj

ek-09386075289

मो० अरशद

C;qjks phQ

eऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।

आर.एन.आई UPHIN/2010/32566

सम्पादक

आरती पाण्डेय

मो.9415087228

9889745884. 9807059191. 9026560178

Email- adbhutsamachar@yahoo.in adbhut_samachar@rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक